राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास का प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र
वार्षिक मूल्य : 1100 रुपये

RNI No. : DELBIL/2013/49657

www.grameenworld.in

Editor
Sangeeta Sharma
09999625733

ग्रामीण वर्ल्ड
GRAMEEN WORLD

वर्ष : 13 अंक : 02 नई दिल्ली 08 से 14 जून 2024 पेज : 8 Email: editor.grasmeenworld@gmail.com

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) के संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के रिकार्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में श्री मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। श्री मोदी के शपथ लेते ही समूचा आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा। श्री मोदी ने हिन्दी में शपथ ली। उनके साथ उनकी भारी भरकम मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ली जिनमें 30 केबिनेट , पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 30 से अधिक राज्य मंत्री शामिल हैं। श्री मोदी इससे पहले 2014 और 2019 में लगातार दो कार्यकाल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने श्री नेहरू के रिकार्ड को दोहराकर इतिहास रचा है। वर्ष 1962 के बाद यह दूसरा मौका है जब किसी नेता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राजग ने 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 293 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है हालाकि इस बार भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है और उसे 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है।

शपथ लेने वाले केबिनेट मंत्रियों में सर्वश्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, डॉ एस जयशंकर, मनोहर लाल,एच डी कुमारस्वामी,पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान,जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, सवार्नंद सोनोवाल,वीरेन्द्र कुमार, राम मोहन नायडू , प्रह्लाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेन्द्र यादव,गजेन्द्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, डा मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी,चिराग पासवान, सी आर पाटिल शामिल हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में सात पड़ोसी नेताओं से मुलाकात की मोदी ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आये पड़ोस के सात देशों के नेताओं को आज आश्वासन दिया कि भारत उनके साथ घनिष्ठ साझीदारी में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मेहमान नेताओं से मुलाकात की। नेताओं ने उन्हें ऐतिहासिक लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए, अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और 'सागर विजन' के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उप राष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ से भी अलग से मिले। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने तीसरे कार्यकाल में, भारत देशों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा, यहां तक कि वह 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा।

मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को दी नसीहत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय वर्ष के समापन समारोह में ऐसी बातों का खुलासा किया है, जिससे भाजपा और संघ के बीच तालमेल को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भागवत ने बिना नाम लिए मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मणिपुर पिछले एक साल से शांति की राह देख रहा है। प्राथमिकता के साथ उसका विचार करना होगा। वह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों का युद्ध की तरह लड़ा गया। भागवत ने कहा कि जिस तरह से चुनाव में चीजें हुई हैं, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। सभी की पूजा का सम्मान करना है, ये मान कर चलना है कि हमारे जैसा उनका धर्म भी सच्चा है। भागवत के इन सब खुलासों के बाद मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि भाजपा और संघ के रिश्तों में कहीं न कहीं तनाव नजर आता है और संघ कई मुद्दों पर नाराज दिखाई देता है।

स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली, लेकिन पिछली सरकार के कई अहम मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। जिनमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव जीतने बाद भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नारायण राणे, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि कैबिनेट में जगह नहीं पाने वालों में अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, आर के सिंह, महेंद्र नाथ पांडेय का भी नाम है जो चुनाव हार गये हैं। पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे, जनरल वी के सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, दर्शना जरदोश, वी मुरलीधरन और मीनाक्षी लेखी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बराला और निशीथ प्रमाणिक को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है।

कृषि वैज्ञानिक छोटे किसानों के हित में काम करें: कृषि मंत्री

नई दिल्ली: कृषि वैज्ञानिक छोटे किसानों के हित में काम करें: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह झ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (क्अफ्क) के पूर्व छात्र सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की कि वे छोटे और सीमांत किसानों के हित में कार्य करें और भारतीय कृषि में क्रांति लाएं।

भारतीय कृषि में छोटे किसानों की भूमिका

श्री चौहान ने कहा कि हमारे देश में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। हमें ऐसा कृषि मॉडल बनाना होगा जिससे किसान एक हेक्टेयर तक की खेती में भी अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकें। उन्होंने भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री चौहान ने कहा, हमें ऐसा रोडमैप बनाना होगा, जिससे भारतीय कृषि और किसानों का कल्याण हो सके और हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बना सकें। हमें दुनिया को अन्न खिलाने और निर्यात करने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने उन्नत तकनीकी को अपनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह बदलना उनकी जिद है और वे किसान और विज्ञान को जोड़ना चाहते हैं। हमें किसानों को विज्ञान से जोड़ना है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं,ह्व इस महत्वपूर्ण बैठक में डॉ. आर.एस. परोदा, पूर्व महानिदेशक क्ळअफ, डॉ. रमेशचंद, सदस्य नीति आयोग और डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव ऊअफए और महानिदेशक क्ळअफ ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। क्अफ्क के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह और DDG डॉ. आर.सी. अग्रवाल भी उपस्थित थे।

भविष्य की दिशा

डॉ. परोदा ने भारतीय कृषि को नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता से उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें किसानों के साथ मिलकर नई तकनीकों का परीक्षण और कार्यान्वयन करना होगा, जिससे उनकी पैदावार और आय में वृद्धि हो।

डॉ. रमेशचंद ने कहा कि नीति निर्माण में किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूंढना अनिवार्य है। हमें कृषि नीतियों को छोटे और सीमांत किसानों के अनुकूल बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नवीनतम तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर सकें, उन्होंने कहा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को इन फसलों के लिए 100% खरीद का दिया आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में महत्वपूर्ण बैठक कर देश में दलहन की आत्मनिर्भरता पर 8 राज्यों के मंत्रीगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में राज्यों के साथ चर्चा करके प्लानिंग करने का यह उपयुक्त समय है. भारत सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयात में अग्रणी देश है. 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में दलहन 270.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं, जिसमें 907 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पर 244.93 लाख टन उत्पादन होता है. यह 2015-16 की तुलना में 50% ज्यादा है. मैं इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद करने के लिए राज्यों के सामूहिक प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं, परंतु हम और बहुत कुछ कर सकते हैं.

संपादकीय

आशा है मिलजुलकर काम करेगी नई सरकार

संगीता शर्मा

सरकार गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास लौट आया है। नतीजों से जो सेटबैक लगा था वे उससे उबर गए दिखते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सहयोगी पार्टियों को हैंडल किया है। अपने हिसाब से उनको मंत्री पद दिए हैं और कामचलाऊ विभाग देकर उनको निपटाया है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि तीसरी सरकार भाजपा के या स्वंय मोदी के एजेंडे से नहीं चलेगी, बल्कि गठबंधन के एजेंडे से चलेगी। भले गठबंधन की सरकार में 82 फीसदी सांसद भाजपा के हैं और वह उस तरह से सहयोगी पार्टियों पर निर्भर नहीं है, जैसी मनमोहन सिंह की सरकार थी या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके बावजूद मोदी को कामकाज में बहुत संतुलन बनाने की जरुरत होगी क्योंकि दूसरी ओर विपक्ष भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत और एकजुट है। तभी ऐसा लग रहा है सरकार तमाम विवादित एजेंडे को स्थगित कर सकती है। हालांकि मुश्किल यह है कि भाजपा को भी राज्यों में चुनाव लड़ना है और पांच साल बाद अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच जाना होगा। तभी यह देखना दिलचस्प होगा कि विवादित मुद्दों या जिन मुद्दों पर आम सहमति नहीं है उनको लेकर सरकार का क्या रुख होता है। सरकार उसे ठंडे बस्ते में डालती है या सहयोगियों पर दबाव बना कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती है ?सरकार के लिए सबसे पेचीदा मामला परिसीमन और महिला आरक्षण का हो गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में नारी शक्ति वंदन कानून पास कराया। संसद की नई इमारत में यह पहला कानून था, जिसका बिल पेश किया गया था। मोदी सरकार ने इस बिल को उस रूप में पेश नहीं किया, जिस रूप में इसे पहले एक सदन की मंजूरी मिल चुकी थी। सरकार नया मसौदा ले आई, जिसमें यह शर्त जुड़ी हुई है कि परिसीमन के बाद 2029 में महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण से किसी को समस्या नहीं है। सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियों के अलावा विपक्षी पार्टियां भी महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन परिसीमन का विरोध तय है। विपक्ष के साथ साथ सरकार की कई सहयोगी पार्टियां भी परिसीमन का विरोध कर सकती हैं। अभी तक यह कहा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा, जिसमें दक्षिण भारत से लोकसभा सीटों की संख्या कम हो सकती है और उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ सकती हैं। तभी दक्षिण भारत की पार्टियां जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध करती हैं। ध्यान रहे आंध्र प्रदेश की टीडीपी और कर्नाटक की जेडीएस दोनों सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन परिसीमन पर इनका समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा। सो, यह सरकार को उलझाने वाली स्थिति है और उसने तय किया हुआ है कि 2029 के चुनाव तक परिसीमन हो जाएगा और महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसी तरह भाजपा ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का वादा किया है। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसे अपने राज्य में लागू कर दिया है। भाजपा ने इसे अपने चुनाव घोषणापत्र में भी शामिल किया है और इस बार के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक सभी इसका वादा करते रहे हैं। लेकिन सरकार बनने से पहले ही भाजपा की सहयोगी जनता दल यू ने कहा कि इस पर सबकी सहमति बनाने की जरुरत है। ऐसा लग रहा है कि धर्म के मामले में दखल देने वाला कोई भी कानून लाना अब संभव नहीं होगा। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बातें भी ठंडे बस्ते में जाएंगी क्योंकि जनता दल यू और टीडीपी दोनों इसके पक्ष में हैं। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं कभी नहीं कहा गया है कि लेकिन उसके समर्थक वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव और धर्मस्थल कानून की समाप्ति की बात भी कर रहे थे। कहा जा रहा था कि चार सौ सीटें आएंगी तो वक्फ बोर्ड कानून को बदल कर वक्फ की सारी संपत्ति सरकार ले लेगी और नरसिंह राव सरकार के समय बना धर्मस्थल कानून बदल दिया जाएगा ताकि कथित तौर पर हिंदू मंदिरों के स्थान पर बने मस्जिदों को वापस हासिल किया जा सके।

नई सरकार से मजबूत होगी आर्थिकी

-डा. जयंतीलाल भंडारी-

चार जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बनने वाली एनडीए के तीसरे कार्यकाल की नई सरकार देश को आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से देश को एक बेहतर आर्थिक परिवेश के साथ बेहतर मानसून की सौगातें विरासत में मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। स्थिति यह है कि देश की बेहतर आर्थिकी के परिप्रेक्ष्य में दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि भारत में कोई भी सरकार बने, अब आर्थिकी तेज गति से मजबूत होगी। खास बात यह भी है कि 7 जून को एनडीए के संसदीय बोर्ड की बैठक में जिस तरह से गठबंधन के समर्थक नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराहना दी गई और विकसित भारत के लिए हर तरह का योगदान देने का संकल्प दोहराया गया, उससे निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति से आगे बढ़ेगी। उल्लेखनीय कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसदी रहने संबंधी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक आर्थिक व वित्तीय बाजार मजबूत हो रहे हैं। भारत के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों के दमदार बही-खाते भारत की आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश, वैश्विक आर्थिक संगठनों के द्वारा भारत के विकास के नए-नए प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सबके साथ-साथ नई सरकार से देश की अर्थव्यवस्था को नई शक्ति मिलने की संभावनाओं से देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ने के शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रही है।

गौरतलब है कि हाल ही में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएेंडपी ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, तेज आर्थिक सुधार और बढ़ती राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 फीसदी सालाना रही है और अब यह विकास दर अगले तीन साल में लगातार 7 फीसदी के करीब होगी। दुनिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत की विकास दर को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर बढ? संबंधी अन्य महत्वपूर्ण नई रिपोर्टों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 7 प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत विकास दर रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं। देश और दुनिया के प्रमुख अर्थ विशेषज्ञों का मत है कि भारत की विकास दर आगामी दशक तक 6.5 से 7 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई देगी। विभिन्न आर्थिक रिपोर्टों में इस बात को भी रेखांकित किया जा रहा है कि भारत में वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) संग्रह 17.7 फीसदी बढकर 19.58 लाख करोड रुपए हो गया है। इसी तरह से 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उच्चतम स्तर पर रहा है। इसका आकार 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 फीसदी अधिक है। कर संग्रह के ये चमकीले आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दशार्ते हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के द्वारा हाल ही में भारत सरकार के लिए अब तक के सबसे अधिक लाभांश की राशि सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर देश के शेयर बाजार ने पिछले 10 वर्षों में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उससे दुनिया भर में भारत के नए तेज विकास की नई संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए लाभांश देने की मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों के लाभांश से 1.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया था। ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लाभांश बजट अनुमान की तुलना में 107 फीसदी ज्यादा है। यह एक तरह से सरकार के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1.09 लाख करोड़ रुपए के अप्रत्याशित लाभ जैसा है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने पहली बार आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 6 फीसदी था। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, इसीलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर बढ़ाकर 6.5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को रिकॉर्ड लाभांश के दिए जाने के निर्णय और वैश्विक आर्थिक संगठनों व वैश्विक क्रेडिट एजेंसियों के द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की ऊंची विकास दर के अनुमानों के बाद भारतीय शेयर बाजार को लाभ मिला। यह उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार और निवेशकों को उम्मीद थी कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों से भाजपा और एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी, लेकिन चुनाव में भारी अनुमान के मुताबिक ऊंचाई नहीं होने के कारण शेयर बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं।

फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं है कि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंचने के साथ ही भारत इस मुकाम तक पहुंचने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है। कोरोना काल के बाद भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की रुचि शेयर बाजार में बढ़ी है। साथ ही पिछले 10 साल में डीमेंट अकाउंट 2.3 करोड़ से बढकर 15 करोड़ हो गए हैं और म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या एक करोड़ से बढकर 4.5 करोड़ हो गई है। स्थिति यह है कि पिछले 10 साल में शेयर बाजार कहां से कहां पहुंच गया है। लाखों छोटे निवेशक आज उत्साहपूर्वक बाजार से जुड़े हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार है और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी भारत के शेयर बाजार पर बढ़ा है। अब ऐसी आर्थिक मजबूती से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाएगा और वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत के प्रति बढ़ते आर्थिक आकर्षण से न केवल देश में ज्यादा एफडीआई लाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह विदेशी कंपनियों और निवेशकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करेगा कि वे भारत से हुई कमाई को फिर भारत में ही निवेश करने के लिए तत्पर रहें।

इससे भारत में कारोबारी माहौल में सुधार होगा। यह सुधार उन घरेलू निवेशकों को भी बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा जो अभी किनारे बैठकर निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Editorial team

Sangeeta, Sharma
Chief Editor

Arun Nishana
Metro Editor

Rajendra Jain
Resident Editor

Mr Raneesh Perambra Editor

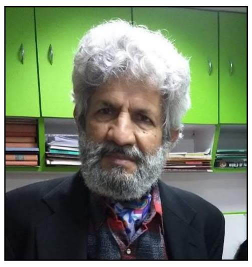

S K Jain
Special Correspondent

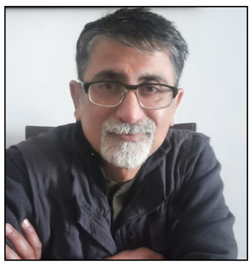

Sudeep Kapoor
Chief Photographer

Dr Nem Singh Premi News Editor

Aslam Ansari
Graphic Designer

Advisor

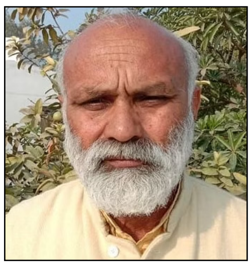

Padma Shri Kanwal Singh Chauhan

Dhyanacharya Dr Ajay Jain

Dr Dipendra Chahar

Dr Sain Dass-Scientist

मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का किया गया बंटवारा

शिवराज को कृषि, खट्टर को आवास, शाह-गडकरी समेत पांच वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शपथ के बाद आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का वितरण भी हो गया है। बड़े मंत्रियों के विभागों में बदलाव नहीं हुआ है।

रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय पहले की ही तरह राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और डॉ एस. जयशंकर के पास ही रहेगा। इसके अलावा नितिन गडकरी पहले की तरह सड़क परिवहन मंत्रालय देखेंगे। बतौर राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा उनके मंत्रालय में सहयोगी मंत्री होंगे।

मोदी कैबिनेट में शामिल शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जेपी नड्डा को इस बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज को कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। खट्टर शहरी विकास और विद्युत मंत्रालय संभालेंगे। नड्डा को मोदी 1.0 की ही तरह स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्री, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, सवार्नंद सोनोवाल बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे। अश्वनी वैष्णव को इस बार सूचना-प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। सहयोगी दलों को भी मोदी कैबिनेट में बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय दिया गया है।

मोदी 3.0 में किसके पास कौन सा मंत्रालय

कैबिनेट मंत्री

राज नाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री। डॉ. एस जयशंकर विदेश मंत्री। मनोहर लाल आवास और शहरी मामलों के मंत्री और विद्युत मंत्री।

एच. डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्री; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। सबार्नंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। डॉ. वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किंजरापु राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री। प्रल्हाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री; और पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉ. मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री; और युवा मामले और खेल मंत्री। जी. किशन रेड्डी कोयला मंत्री; और खान मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। जाधव प्रतापराव गणपतराव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

राज्य मंत्री

जितिन प्रसाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीपद येसो नाइक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। राम नाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री। वी. सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रो. एस. पी. सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। सोभा करंदलाजे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। बी. एल. वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉ. एल. मुरुगन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। दुगार्दास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। तोखन साहू आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। राज भूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। निमूबेन जयंतीभाई बांभनिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। पबित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की

वाराणसी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां मिजार्मुराद के मेंहदीगंज में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में मंगलवार को जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया।

इस दौरान भीड़ ने हर हर महादेव के नारे लगाए। मोदी को योगी ने कंधे पर हल लिए किसान का एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया। तीन किसानों... रमेश साहनी, उदयभानु सिंह और लालबहादुर राम ने प्रधानमंत्री का किसानों की तरफ से स्वागत

किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की। इसके उन्होने ने कृषि सखी प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली कृषि सखियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

मैं बनारस की जनता को नमस्कार करता हूं... पीएम मोदी

चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आया हूं। मैं बनारस की जनता को नमस्कार करता हूं...काशीवासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों के मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं: प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त की जारी

वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17 वीं किस्त के तहत 20 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की। पीएम मोदी इसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे। फिर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता और योगी सरकार के कई मंत्री भी वाराणसी पहुंचे हुए हैं।

हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है- सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए क्लेवर और नई काया के साथ दुनिया भर में अपनी नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। पिछले 10 वर्ष में इस नई काशी के कायाकल्प में न सिर्फ हजारों-करोड़ों रुपए लगे हैं बल्कि दुनिया ने इसे बदलते हुए देखा है।"

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीड़ है और किसान उसकी आत्मा- शिवराज सिंह

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीड़ है और किसान उसकी आत्मा है। भाजपा का मानना है कि किसान भगवान है और किसान की सेवा भगवान की पूजा है... किसान और खेती के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर कोई पहली फाइल साइन की तो किसान सम्मान निधि को किसानों के खाते में डालने की फाइल साइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सांसद के तौर पर काशी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।

A 3 days event of "BHARTIYA PATRKARITA MAHOTSAVA" celebrated and conducted BY @STATE PRESS CLUB, MADHYAPRADESH

A 3 days event of "BHARTIYA PATRKARITA MAHOTSAVA" celebrated and conducted BY @STATE PRESS CLUB, MADHYAPRADESH, which was constantly on a marathon talks on diffrent subjects by Intellectual Press/Media (Print, Electronic & Web) media reporters from whole over the Nation.

On the last day after the talk show on Manav adhikar & media participated by World Chairman Dr. Nem Singh Premi, Dr. Jitendra Matlani, IHRO President UAE & Mr. Battchu Avinash Devi Chandra, IHRO President South Asia, appointed Mr. Sudesh Gupta as President Indore Division & released the Postal Stamp of IHRO

The proud moment of launching the stamp was done by Honorable Minister Shri Kailash Vijayvargiya ji & Shri Tulsi Silawat ji,

Shri Praveen Khariwal President State Press Club, Madhya Pradesh & other dignitaries.

IHRO momento was also given by IHRO World Chairman..

International human rights organisation release IHRO stamp during three days patrakarita Samelan organised by Madhya Pradesh state press club Stamp was released by Shri Kailash Vijayvargiya hon'ble minister of parliamentary affair MP State and Shri Tulsi Ram Silawat hon'ble minister of water resources MP State

In presence of Shri Praveen Praveen Kumar Khariwal president MP State press club Shri Sudesh Gupta Shivhare President IHRO Indore District Dr Jitendra Matlani President UAE IHRO Shri Batchu Avinash Chairman Batchu foundation, Shri Nem Singh Premi II World president IHRO, Shri Sankar Mandal Secretary Maharashtra IHRO

Dr Jitendra Matlani in his speech conveyed Heartfelt Gratitude towards Shri Praveen Khariwal Shri Sudesh Gupta and entire team of MP State press club for all the red carpet reception and the hospitality

#jitendramatlani #pridesofindore #indorediaries #indore #MadhyaPradesh #india

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधिकारिक तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा-अर्चना कर कृषि मंत्रालय का पदभार आज ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कृषि मंत्रालय का औचक निरीक्षण किया।

श्री चौहान ने निरीक्षण के दौरान मंत्रालय के लिफ्टमैन, एमटीएस, क्लर्क स्तर के कर्मचारियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में मौजूद सभी सफाईकर्मी, एमटीएस आदि हमारे साथी है, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर विजट कर महत्वपूर्ण जानकारी भी ली। इस सेंटर में देश के विभिन्न राज्यों की वर्तमान में फसल की स्थिति, क्रॉप वेदर की स्थिति, वर्षा की स्थिति, कम वर्षा या ड्राट एरिया की जानकारी सहित विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त की।

पदभार ग्रहण करने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र सौंपा। संकल्प पत्र देने के बाद श्री चौहान ने कृषि विभाग की टीम को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि मैं ये अंतरात्मा से कह रहा हूं कि काम मेरे लिए पूजा है, दिन-रात मिलकर काम करेंगे। राजनीति हमारे लिए कर्मकांड नहीं, सेवा का माध्यम है। आज मैं मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र आपको सौंप रहा हूं, इसे हर हाल में हमें पूरा करना है। एक - एक क्षण का उपयोग करना है। मोदी जी विजनरी लीडर है, उनके मार्गदर्शन में संकल्प पत्र में दिए कार्यों को समय के साथ पूरा करने के रोडमैप पर सभी काम करे। यह आपका सौभाग्य है कि आप सब देश के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। देश का भविष्य और भाग्य बदलने का काम आप कर रहे हैं। भारत कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहा है, इसे और बेहतर करना है, अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करना है। काम कोई एक या तीन मंत्री नहीं करते, पूरी टीम मिलकर काम करती है, कमिटमेंट के साथ करती है। हमारे विभाग का नाम कृषि के साथ

किसान कल्याण है, मतलब अन्नदाता का कल्याण, उनकी जिंदगी बदलना ही हमारा मिशन है। हमें अपनी टीम के हर सदस्य का, टीम के टेलेंट का सर्वोच्च उपयोग करना है। जो अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मार्गदर्शन लेना है। हम करोड़ों-करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था रहे है, यह मैं पहले दिन से कह रहा हूं। मैं आपका सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं, मैं सब चीजें समझे बिना दिल्ली नहीं छोड़ूगा। मुझे पूरी जानकारी चाहिए।

श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी ने भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। माननीय मंत्रियों का स्वागत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा, डेयर के सचिव श्री हिमांशु पाठक और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से संविधान व लोकतंत्र को खतरा : सीएम योगी

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को गोरखपुर में आपातकाल के 50वें वर्ष के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी एवं लोकतंत्र रक्षक सम्मान कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए।

- आपातकाल पर काला दिवस विषयक संगोष्ठी और लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री
- आपातकाल लोकतंत्र की कुचलने की पराकाष्ठा थी : सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की आस्था कभी भी भारत के संविधान और लोकतंत्र में नहीं रही है। जब भी उसे मौका मिला, उसने संविधान का गला घोंटने और लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया है। जब मौका नहीं मिला तो उसने संविधान और लोकतंत्र की ही दुहाई देकर जनता को झूठी बातों से गुमराह किया। वास्तविकता यही है कि आज भी संविधान और लोकतंत्र को खतरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दलों से है।

सीएम योगी देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल (इमरजेंसी) के पचासवें वर्ष में मंगलवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा की जिला व महानगर इकाई की तरफ से आयोजित काला दिवस विषयक संगोष्ठी और लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 28 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य रात्रि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा था। देश के संविधान का गला घोंटकर, आपातकाल लागू कर कांग्रेस ने लोकतंत्र को तहस नहस करने की कुचेष्टा की थी। इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे, न्यायालयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जिन लोगों ने इस तानाशाही रवैये के विरोध किया, उन्हें जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। कांग्रेस के इस कृत्य से संविधान कराह उठा था, लोकतंत्र तड़प गया था। यह लोकतंत्र को कुचलने की पराकाष्ठा थी।

कांग्रेस का सिर्फ चेहरा बदला है,चरित्र नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस का बर्बर चेहरा हम सभी को देखने को मिला था। उसने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय आवाज उठाने पर अटल बिहारी वाजपेयी, जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के सभी नेताओं और लोकतंत्र समर्थकोंको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सीएम ने कहा कि आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही चेहरा बदला हो लेकिन आज सत्ता से बाहर होकर भी उसका मूल चरित्र वही है जो आपातकाल के समय था।

जब भी अवसर मिला, कांग्रेस ने घोंटा संविधान और लोकतंत्र का गला

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उसने लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने से परहेज नहीं किया। स्वतंत्र भारत में जो संविधान एकता और एकात्मकता के लिए अंगीकार किया गया था, उसमें कुछ दिनों बाद ही जबरन धारा 370 लाकर कांग्रेस ने कश्मीर में आतंकवाद की नींव रख दी। तुष्टिकरण की पोषक धारा 370 नहीं होता तो कश्मीर में आतंकवाद और विस्थापन की समस्या नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1950 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकारों ने स्वार्थ पूर्ति के लिए 75 से अधिक संशोधन किए। कांग्रेस ने धारा 356 का इस्तेमाल कर 90 बार से अधिक राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व भावी पीढ़ी को कांग्रेस के कुकृत्य से अवगत कराने की जरूरत है ताकि फिर किसी पीढ़ी को आपातकाल की तरह अपनी जवानी होम न करनी पड़े। सीएम ने आज सम्मानित होने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के जज्बे को नमन करते हुए कहा कि उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।

कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों ने चुनाव में जनता को गुमराह किया

सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का झूठ गढ़कर, फर्जी बॉन्ड का वादा कर जनता को गुमराह किया। हकीकत तो यह है कि जब भी मौका मिला कांग्रेस ने एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तुष्टिकरण के नाम पर एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग आज संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये लोग भारत के बाहर जाकर भारत को और उसके लोकतंत्र को कोसते हैं।

जिन दलों के संस्थापकों ने किया आपातकाल के खिलाफ आंदोलन, कांग्रेस की गोद में जा बैठी आज की पीढ़ी

सीएम योगी ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1975 में देश के लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन दलों के संस्थापकों, नेताओं ने आंदोलन किए, जेल की यातनाओं को सहा था, लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, दुखद है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी नीतियों की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस के सहयोगी दलों के पूर्वज आज कहीं से अपनी पार्टी के वर्तमान नेताओं को कांग्रेस के साथ देखते होंगे तो वे खून के आंसू पीने को मजबूर होते होंगे।

इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानी शीतल पांडेय ने आपातकाल से जुड़े अपने संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम में एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, विधायक विपिन सिंह, महेन्द्रपाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ल, भाजपा महानगर महामंत्री ओमप्रकाश शर्मा, छोटेलाल मौर्य, मनोज शुक्ल, अच्युतानंद शाही आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

इन लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सीएम योगी ने किया सम्मान

शीतल पांडेय, रमेश विश्वकर्मा, योगेंद्र गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, डॉ. केशव सिंह, शिव प्रकाश अग्रवाल, राजाराम, दीप नारायण शुक्ला, सुरेश खन्ना, डॉ. महेश पाठक, राजकिशोर मिश्र, दुर्गा प्रसाद मिश्र, भगवती सिंह, छेदी लाल, धनराज सिंह, शंभू सिंह श्रीनेत, राजेश गुप्ता, क्षत्रपति शुक्ला, हरिलाल चौरसिया, शेषनाथ सिंह,, बलदेव यादव, श्रीकृष्ण गुप्ता, नागेंद्र सिंह, रामेश्वर सिंह, नरेंद्र यादव, लालजी सिंह, अभिमन्यु शाही, हेमंत सिंह, विनय प्रणाचार्य, अभय पांडेय, अभिमन्यु सिंह, रामनरेश।

Yogi Cabinet's nod to ordinance seeking to curb question paper leaks in UP

Up to Rs 1 crore fine, life imprisonment proposed for those involved in paper leaks
Yogi govt takes firm step to conduct examinations in a transparent and fair manner in UP
Yogi cabinet approves the Prevention of Unfair Means and Paper Leak in Public Examinations 2024 Ordinance
43 out of 44 proposals were approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath

Lucknow
An ordinance to prevent unfair practices and paper leaks in public examinations was approved in a cabinet meeting held at Lok Bhavan on Tuesday, chaired by Chief Minister Yogi Adityanath.

This ordinance includes stringent penalties for violators, with punishments ranging from 2 years to life imprisonment and fines of up to one crore rupees.

Notably, the Yogi government has previously implemented strict measures against paper leaks, and this ordinance is another significant step in that direction.

Following the Council of Ministers meeting at Lok Bhavan, Finance and Parliamentary Minister Suresh Khanna provided details about the approved proposals. He said, "A total of 44 proposals were presented to the Cabinet of which 43 were approved. Among the approved proposals was the Prevention of Unfair Means and Paper Leaks in Public Examinations Ordinance 2024."

According to the Finance Minister, this ordinance mandates severe penalties for those involved in paper leaks, including institutions and associated individuals, with punishments ranging from 2 years to life imprisonment and fines of up to one crore rupees.

The ordinance covers the Public Service Commission, Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board, Uttar Pradesh Board, universities, authorities, or institutions nominated by them.

It applies to all recruitment examinations, regularization or promotion exams, and entrance exams for degrees, diplomas, or certificates.

The ordinance also criminalizes the distribution of fake question papers and the creation of fake employment websites.

He said, "If an examination is compromised, the financial burden will be recovered from the solver gang, and the involved institutes and service providers will be permanently blacklisted. The Act also includes provisions for property attachment in case of crime. All offences under this ordinance are classified as cognizable, non-bailable, and triable by the Sessions Court and are non-compoundable. Stringent conditions for bail have also been established."

He added, "In the absence of an Assembly session, an ordinance has been proposed in place of a bill. The Council of Ministers will approve the proposal, after which the ordinance process will be completed and implemented."

Chief Minister Tourism Fellowship Program also gets Cabinet nod

The Yogi Cabinet has approved the Chief Minister Tourism Fellowship Program, which aims to select researchers through the Tourism Department. These researchers will promote tourism in the state and facilitate investment acceleration in this sector. Additionally, they will assist in resolving issues faced by investors. Tourism Minister Jaiveer Singh highlighted these researchers' pivotal role in supervising and monitoring Tourism Department schemes, developing ecological sites comprehensively, evaluating both central and state government schemes, and advancing plans for fairs and festivals. They will contribute significantly to creating a favourable environment for investors and tourists while supporting the preservation efforts of the District Tourism and Culture Council, particularly under the Tourism Directorate. Initially, 25 researchers will be chosen for this program. They will receive an honorarium totalling Rs. 40,000, with Rs. 30,000 allocated for remuneration and Rs. 10,000 for field visits. Additionally, they will be provided with a tablet for their work.

Boundaries of three development authorities expanded

The Yogi government has also approved extension of the Varanasi, Bareilly, and Moradabad development authorities with inclusion of several revenue villages. Finance Minister Suresh Khanna informed that with the proposed extension, the Varanasi Development Authority. will include 215 revenue villages.

Similarly, 35 revenue villages have also been included in the Bareilly Development Authority and 71 revenue villages in the Moradabad Development Authority.

Tata Sons to build Indian Temple Museum in Ayodhya

Tourism Minister Jaiveer Singh informed that Tata Sons will construct a world-class Indian Temple Museum in Ayodhya with an investment of Rs 750 crore from its CSR fund. The cabinet has approved the proposal for the world-class museum.

The Government of India has collaborated with Tata Sons on this initiative, earmarking Rs 650 crore for the museum and another Rs 100 crore for ancillary development. Rs 750 crore has been sanctioned for the Indian Temple Museum project. Tata Sons will oversee the construction, with the Tourism Department leasing the land at a nominal rate of one rupee for a period of 90 + 90 years.

झीलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर झाडौल तहसील में आवारगढ़ की पहाडियों पर शिवजी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है जो की कमलनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वंय लंकापति रावण ने की थी। यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव नें रावण की नाभि में अमृत कुण्ड स्थापित किया था। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है की यहां भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है क्योकि मान्यता है की शिव से पहले यदि रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी पूजा व्यर्थ जाती है।

कमलनाथ महादेव

यहां शिव से पहले की जाती है रावण की पूजा

पुराणो में वर्णित कमलनाथ महादेव की कथा-

एक बार लंकापति रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे, उसके कठोर तप से प्रसन्न हो भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग डाला। भगवान शिव लिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए, उन्होंने रावण को एक शिव लिंग दिया और यह शर्त रखी कि यदि लंका पहुंचने से पहले तुमने शिव लिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लम्बा था, रास्ते में रावण को थकावट महसूस हुई और वह आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। और ना चाहते हुए भी शिव लिंग को धरती पर रखना पड़ा।

आराम करने के बाद रावण ने शिव लिंग उठाना चाहा लेकिन वह टस से मस ना हुआ, तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह वहीं पर पुनः तपस्या करने लगे। वो दिन में एक बार भगवान शिव का सौ कमल के फूलों के साथ पूजन करते थे। ऐसा करते-करते रावण को साढ़े बारह साल बीत गए। उधर जब ब्रह्मा जी को लगा कि रावण की तपस्या सफल होने वाली है तो उन्होंने उसकी तपस्या विफल करने के उद्देश्य से एक दिन पूजा के वक्त एक कमल का पुष्प चुरा लिया। उधर जब पूजा करते वक्त एक पुष्प कम पड़ा तो रावण ने अपना एक शीश काटकर भगवान शिव को अग्नि कुण्ड में समर्पित कर दिया। भगवान शिव रावण की इस कठोर भक्ति से फिर प्रसन्न हुए और वरदान स्वरुप उसकी नाभि में अमृत कुण्ड की स्थापना कर दी। साथ ही इस स्थान को कमलनाथ महादेव के नाम से घोषित कर दिया।

पहाड़ी पर मंदिर तक जाने के लिए आप नीचे स्थित शनि महाराज के मंदिर तक तो अपना साधन लेके जा सकते है पर आगे का 2

किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा करना पड़ता है। इसी जगह पर भगवान राम ने भी अपने वनवास का कुछ समय बिताया था।

ऐतिहासिक महत्व भी है आवरगढ़ की पहाडियों का-

झालौड़ झाला राजाओ की जागीर था। इसी झालौड़ से 15 किलोमीटर की दुरी पर आवरगढ़ की पहाडियों पर एक किला आज भी मौजूद है इसे महाराण प्रताप के दादा के दादा महाराणा ने बनवाया था यह अवारगढ़ के किले के प्रसिद्ध है। जब मुग़ल शासक अकबर ने चितौड़ पर आक्रमण किया था, तब आवरगढ़ का किला ही चित्तौड़ की सेनाओं के लिए सुरक्षित स्थान था। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था। हल्दी घाटी के समर में घायल सैनिकों को आवरगढ़ के इसी किले में उपचार के लिए लाया जाता था। इसी हल्दीघाटी के युद्ध में महान झाला वीर मान सिंह ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाये थे।

झालौड़ में सर्वप्रथम यही होता है होलिका दहन-

हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात झाडौल जागीर में स्थित पहाड़ी पर जहाँ आवरगढ़ का किला स्थित है, वहीं पर सन 1577 में महाराणा प्रताप ने होली जलाई थी। उसी समय से समस्त झालौड़ में सर्वप्रथम इसी जगह होलिका दहन होता है। आज भी प्रतिवर्ष महाराण प्रताप के अनुयायी झालौड़ के लोग होली के अवसर पर पहाड़ी पर एकत्र होते है जहाँ कमलनाथ महादेव मंदिर के पुजारी होलिका दहन करते है।

इसके बाद ही समस्त झालौड़ क्षेत्र में होलिका दहन किया जाता है। झाडौल के लोगों की होली देश के अन्य लोगों को प्रेरणा देती है, कि कैसे हम अपने त्यौहारों को मानते हुए अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद रख सकते हैं।

सोयाबीन की कृषि कार्यमाला

बीजोपचार

बीज को फफूंदनाशक दवा थायरम 75 डब्ल्यू.पी. एवं कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यू.पी. दवा को 2:1 के अनुपात में मिलाकर 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या थायरम 37 प्रतिशत + कार्बाक्सिन 37 प्रतिशत, 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से या ट्राइकोडर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं।

उर्वरक एवं खाद

सामान्यतः 40 कि.ग्रा. यूरिया, 375 कि.ग्रा. फास्फोरस एवं 70 कि.ग्रा. पोटाश की मात्रा का उपयोग करें।

बुवाई का तरीका

कतार से कतार की दूरी 45 से.मी. हो । कम ऊंचाई वाली जातियों या कम फैलने वाली जातियों को 30 से.मी. की कतार से कतार की दूरी पर बोयें। बुवाई का कार्य दुफन, तिफन या सीडड्रिल से ही करें।

मेढ़– नाली विधि एवं चौड़ी पट्टी–नाली विधि से बुवाई करने से सोयाबीन की पैदावार में वृद्धि पायी गयी है। एवं नमी संरक्षण तथा जल निकास में भी प्रभावी पायी गयी है।

अधिक फैलने वाली जातियों की 3 से 4 लाख के आसपास पौध संख्या एवं कम फैलने वाली जातियों की 4 से 6 लाख पौध संख्या प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।

सामान्य तरीके से बुवाई के बाद 20–20 मीटर की दूरी पर ढाल के अनुरूप जल निकास नालियाँ अवश्य बनायें, जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में जल भराव की स्थिति पैदा न हो। मेढ़–नाली विधि एवं चौड़ी पट्टी–नाली विधि की बुवाई, जल निकास में भी प्रभावी पायी गयी हैं।

खरपतवार नियंत्रण

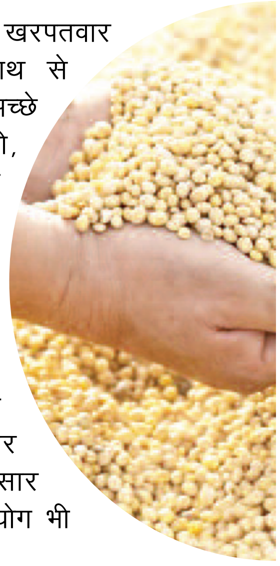

20–25 दिन में फसल से खरपतवार निकाल दें। मजदूरों द्वारा हाथ से निंदाई करवाने के परिणाम अच्छे मिले हैं। परंतु मजदूरों की कमी, वर्षा का अंतराल एवं जमीन की स्थिति से हाथ की निंदाई खरीफ मौसम में कभी–कभी कठिन हो जाती है अतः यांत्रिक विधियों में सी.आई.ए.ई. भोपाल द्वारा निर्मित उन्नत हैंड हो या बैलों से चलने वाला कुल्पा या डोरा से भी नींदा नियंत्रण कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार रसायनिक नींदानाशकों का उपयोग भी करें।

लाभकारी अंतरवर्तीय फसलें

सोयाबीन+मक्का (चार कतारः दो कतार)
या सोयाबीन+अरहर (चार कतार : दो कतार)
या सोयाबीन+ज्वार (चार कतार : दो कतार)
या सोयाबीन + कपास (चार कतार : एक कतार)

लाभकारी फसल चक्र

सोयाबीन गेहूं, सोयाबीन–अलसी, सोयाबीन – चना, सोयाबीन – आर्किल मटर

कटाई, गहाई एवं भंडारण

फसल की कटाई तब करें जब 95 प्रतिशत फलियां भूरी पड़ जायें और पत्तियाँ झड़ जायें।

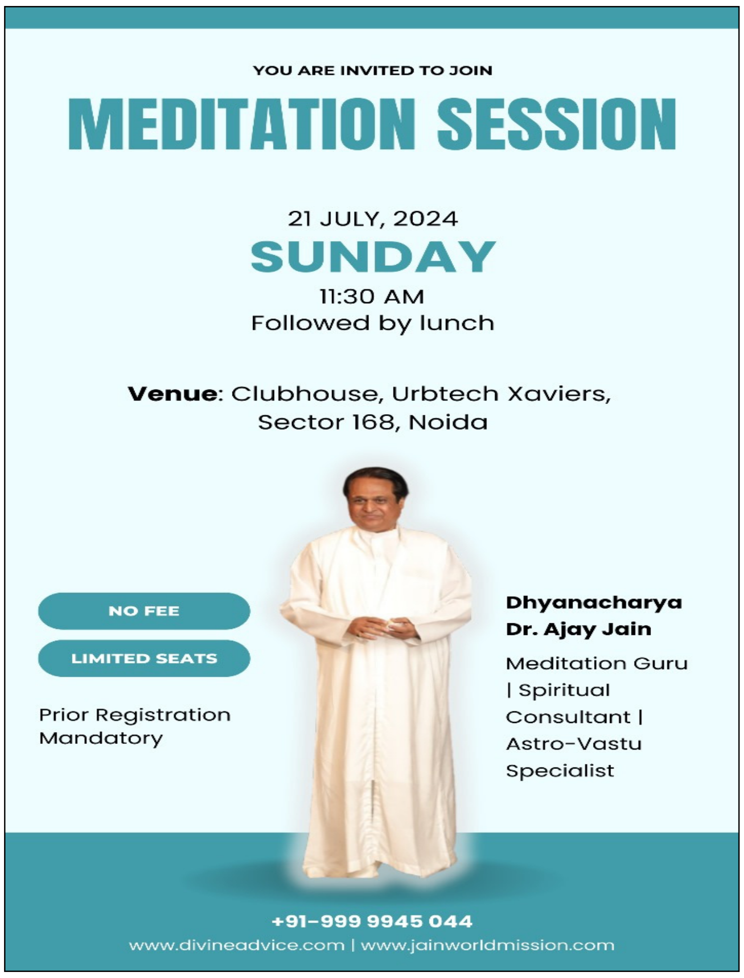

कण-कण में चेतना

समस्त सृष्टि के मूल में एक ही शक्ति या चेतना है, वह चेतना जब जड़ पदार्थो से संयोग करती है, तो जीवों के रूप में व्यक्त होती है और जब ब्रह्मांड व्यापी हो जाती है, तो उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। वस्तुतः शास्त्रों के अनुसार जो सर्वव्यापी है वही अणु में है, जो ब्रह्मांड में है वह कण में भी है। आत्मा, जिसे शरीर तक सीमित रहने वाली चेतना का एक कण समझा जाता है, विकसित होकर परमात्मा के समान विभूतियों की भंडार बन जाती है। आज वैज्ञानिक भी जगत के कण-कण में व्याप्त उस चेतना के अस्तित्व की पुष्टि करने लगे हैं, जिसे धर्म परमसत्ता कहता है। इस परम चेतना के वास्तविक स्वरूप तक तो विज्ञान नहीं पहुंचा है, पर जहां तक भी उसे सफलता मिली है, उससे यह सत्य साफ नजर आ रहा है कि विज्ञान और धर्म समन्वय की ओर बढ़ रहे हैं। चेतना के विषय में धर्म और विज्ञान ने काफी कुछ वर्णन किया है।

ऋग्वेद के अनुसार, एक ही देव विश्व को उत्पन्न करते हैं, देखते व चलाते हैं। उनकी शक्ति सर्वत्र समाई हुई है। वही परम शक्तिमान और कमार्नुसार फल देने वाला है। उपनिषदों में प्रमुख ईशवास्योपनिषद में

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित जगत्यां जगत कहकर विश्व की हर वस्तु में ईश्वरीय चेतना होने की घोषणा की गई है। गीता में नैनं छिंदंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः कह कर इसी आत्मा अर्थात चेतना के कभी नष्ट न होने की घोषणा भगवान श्रीकृष्ण ने की है। महान दार्शनिक शंकराचार्य का अद्वैतवाद एक प्रकार से एक ही चेतना के सर्वत्र विराजमान होने के वैदिक दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा अविनाशी है और चैतन्यता उसका प्रधान गुण हैं। महान दार्शनिक कोयरे ने चेतना को नकारने वाले वैज्ञानिकों पर बरसते हुए कहा था कि यह कितनी अजब बात है कि विज्ञान ने हर पदार्थ को मान्यता दी है, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व को ही मानने से इंकार कर दिया है। इमर्सन एवं बर्पले के मत में सारा संसार कहीं से चेतना उधार ले रहा है। जिस तरह किसी बड़े विद्युत घर से बिजली लेकर छोटे-छोटे बल्ब जलने लगते हैं, वैसे ही यह चेतना जीवों में अलग-अलग रूप में दिखाई देती है। विज्ञान का पर्याप्त अध्ययन करने वाले दार्शनिक स्पिनोजा के अनुसार विचार चेतना का प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते। वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार, सृष्टि का कोई कण चेतना से वंचित नहीं है। परमात्मा इसी रूप में सर्वव्यापी है। आइंस्टीन के अनुसार, सृष्टि के मूल में कोई जड़ तत्व नहीं, बल्कि चेतना की सक्रियता ही है। मनुष्य के साथ-साथ पृथ्वी और अन्य नक्षत्र-ग्रहों की भी अपनी एक चेतना है। वह मनुष्य के समान ही कतिपय सिद्धांतों पर कार्य करती है। संपूर्ण संसार की रचना किसी अद्भुत मस्तिष्क द्वारा की हुई प्रतीत होती है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. ईपी विगनर के अनुसार आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से चेतना की व्याख्या नहीं हो सकती।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **संगीता शर्मा** द्वारा सुधीर प्रिंटर्स 454, देशबंधु गुप्ता मार्केट, करोलबाग, नई दिल्ली-05 से मुद्रित एवं फ्लैट नं. 99, सेक्टर-11, पॉकेट-3, द्वारका दिल्ली-110075 से प्रकाशित।
संपाकद- संगीता शर्मा, मो. 9999625733 (प्रकाशित लेखों के लेखकों की राय से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है) किसी भी कानूनी वाद-विवाद की स्थिति में दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगा।